

अनुमति-पत्र

यह अनुमति ल0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत दी जाती है, किन्तु उर्थ यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के संपन्न में किस पर व्यवसायिक/अतिथि-गृह भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा पार्स के मालिक या अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भेदभाव या स्वामित्व के अधिकारों के बेल्ल कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री के0पी0 सिंह व अन्य द्वारा भवन संख्या-170/2 पार्ट पोर्शन आफ प्लॉट नं0-170 & 4 सी.वाई. चिन्तामणि घोष रोड, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अंतर्गत व्यवसायिक/अतिथि-गृह भवन निर्माण की अनुमति हेतु दखिल गवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तियों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. ल0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिनियम/अधिमोक्ष किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में सर्वोच्च संख्या-2.1.8 एवं 3.1.5 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तर्गत (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 2X3 फिट या एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण उचित करना होगा।
4. स्थल पर 05 शब्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों का हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिनियम/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. लोडिंग स्टैक की स्थापना करना होगा।
7. सेक्टर ड्राइविंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् गलत ग्राउण्ड बोर्ड से स्तान्त के पश्चात् ही जम एफ0डी0आर0 अस्तुक्त किया जायेगा।
8. मानचित्र में पीले रंग में दर्शित अक्षमणीय भाग को स्वीकृत मानचित्र द्वारा होने के एक माह के अन्दर ध्वस्त करकर ड्राइविंग को सुचित करना होगा, अन्यथा ड्राइविंग0प्र0 द्वारा स्तान्त ध्वस्त करके इस पर होने वाला व्यय भू-राजस्व के विकास की गति बरत लिया जायेगा।
9. वेरागैन्ट में प्रकाश एवं संयंत्र हेतु पत्रिक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
10. पवित्र में नगर अधिका, नगर निगम इलाहाबाद द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के कम में कोई शुल्क अथवा प्रतिशत आरंभित किये जाते हैं तो वह आवेदक पर बाध्यकारी होगा।
11. भारतीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकृति गाननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्तान्त निरस्त किया जायेगा।
12. यदि आवेदक द्वारा कोई नसत्पूर्ण सूचना/सिपायो नयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो ल0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
13. मकान निर्माण से यदि जाती के सड़क को गटरो अथवा राइफ या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे के पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण बन्द गई हो) को होने लड़े तो पूरकामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि अधिक प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कदम तो पहले ही उसे अपने खर्च से नसम्त करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
14. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 (इम्प्लियमेंट रूलेजिस्ट्रीसी क्रमा 1985) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए, यदि विकास प्राधिकरण को जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
15. यदि मुख्यमन्त्री का उच्च विमान अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो ड्राइविंग0प्र0 द्वारा नियम नुसार ल0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की पुर्णतः धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. आवेदक के विधानुसार विकास प्राधिकरण को नकल की तीन तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवेदक को ही पूर्ण देना होगा तथा छत आगामी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
17. यदि निर्माण में नसत्तर प्लान का उल्लंघन होना पाया गया तो निर्माणकर्ता को ही नई स्वीकृति एवं संपत्ती प्राप्तियों और केंद्र गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उचित अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अस्म की जायेगी।

Handwritten signature and date: 16/4/13, 9853010109

Handwritten signature and official stamp: संयुक्त सचिव/प्र030-मवन, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

